गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए आपसी समन्वय जरूरी

कमलेश चन्द्र जोशी

अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में 2001 से काम कर रहा है। संस्था शिक्षा को सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण औजार मानती है। फाउंडेशन का मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में समता, न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को पोषित किया जा सकता है। संस्था ने अपनी स्थापना के उपरांत 2005 से उत्तराखण्ड में अपना कार्य शुरू किया। कार्य के शुरुआती दौर में उसके काम के फोकस में दो कार्यक्रम – 'कम्प्यूटर एडेड लर्निंग' और 'लर्निंग गारंटी कार्यक्रम' रहे।

कम्प्यूटर एडेड लर्निंग के तहत जहां कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा प्राथमिक शालाओं से परिचित कराना था, वहीं लर्निंग गारंटी कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक शालाओं में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केन्द्रित रहा। लर्निंग गारंटी कार्यक्रम में यह बात निहित थी कि अगर स्कूल की परीक्षा प्रणाली में सुधार होता है तो उसका असर कहीं कक्षा की प्रक्रियाओं के सुधार पर भी पड़ेगा। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों में 'केवल याद करने' की बजाय 'समझ आधारित प्रश्नों' के पूछने पर तरजीह दी गई और मूल्यांकन को शिक्षकों के अपने सीखने का स्रोत भी माना गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं में दक्षता आधारित मूल्यांकन की बात की गई तथा कार्यक्रम को राज्य के दो जिलों उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में लगातार तीन वर्षों तक संचालित किया गया। आगे के वर्षों में इस तरह की मूल्यांकन प्रणाली राज्य के सभी जिलों में लागू करने के प्रयास भी किए गए। लर्निंग गारंटी कार्यक्रम के संचालन से यह बात समझ में आने लगी कि केवल दक्षता आधारित मूल्यांकन से ही स्कूलों में बच्चों के सीखने–सिखाने और कक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती, जब तक कि स्कूल से जुड़ी संदर्भ संस्थाओं को प्रभावी न बनाया जाए तथा शैक्षिक कार्मिकों व शिक्षकों के सतत क्षमतावर्धन के प्रयास न किए जाएं।

इसके लिए 2008 में लर्निंग गारंटी कार्यक्रम के दूसरे चरण में डायट, बी.आर.सी. व सी.आर.सी. के साथ काम शुरू किया गया और बी.आर.सी. को प्रभावी बनाने के प्रयास शुरू किए गए। बी.

आर.सी. स्तर पर अकादमिक गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के संचालन के दौरान फाउंडेशन के अंदर यह बात भी उठने लगी कि अगर वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है तो एक दीर्घकालिक विजन के साथ जिले में काम करना होगा। इसके लिए जिले में एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना की बात सोचनी होगी। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन को कार्यक्रम के अप्रोच से उभरकर संस्थानिक मोड में काम करना होगा।

इस प्रकार 2011 से अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन संस्थान की शुरुआत हुई। इन्हें राज्य व जिले में एक शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास आरंभ किया गया। इस संस्थान के फोकस में शिक्षक–शिक्षा और शैक्षिक नेतृत्व व प्रबंधन के कार्यक्रम रखे गए।

वर्तमान में शिक्षक शिक्षा के तहत शिक्षकों के क्षमतावर्धन के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जिले में उनके लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने व सतत पेशेवर विकास के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। क्षमतावर्धन कार्यक्रम को लेकर सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आदि में संस्थान की सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके अलावा शिक्षकों के सतत विकास को ध्यान में रखकर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के स्वैच्छिक समूह स्थापित किए गए हैं तथा पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक ब्लाक में

शिक्षकों के स्वैच्छिक समूह में करीब पन्द्रह–बीस सदस्य हैं, जिनके साथ नियमित रूप से अकादमिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। ब्लॉक स्तर पर अकादमिक वातावरण विकसित करने के लिए शिक्षक सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। जिले स्तर पर विषयगत शिक्षकों का समूह तैयार करने की दृष्टि से डायट के साथ मिलकर संदर्भ शिक्षक विकास का काम भी शुरू किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों– गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी आदि से जुड़ी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं तथा शिक्षकों के साथ नियमित संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

इसी तरह डायट के सहयोग से शैक्षिक नेतृत्व व प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चयनित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं, जिन्हें आगे चलकर शैक्षिक कार्मिकों के साथ भी संचालित किया जाना है। इसके साथ ही कुछ चयनित प्रधानाध्यापकों के साथ नियमित स्कूल अनुसमर्थन की योजना भी बनाई गई है।

जिले में डायस डाटा के अनुसार इस समय जिले में 772 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 2759 शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में 94081 बच्चे नामांकित हैं। विगत वर्षों से जिले में शिक्षा का अधिकार बिल के प्राविधान लागू किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिर भी यह सुनने में आता ही है कि जिले के कुछ विद्यालयों में अभी भी एकल शिक्षक हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाएं जाएं। विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप हों। सवाल ये भी है कि शिक्षकों को कक्षाओं में पढ़ाने के पर्याप्त दिन नहीं मिलते। अब भी उन्हें बीएलओ ड्यूटी में जाना पड़ता है। इन समस्याओं का निराकरण जरूरी है।

शैक्षिक समुदाय में एक बड़ा मुद्दा यह भी दिखता है कि शिक्षा प्रणाली का शिक्षकों के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो। इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। इसके साथ स्कूलों की सुधार प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। इस पर उनसे नियमित बात की जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। ऐसा सुनने में आता है कि स्कूल अनुश्रवण के दौरान बच्चों से केवल पहाड़ा पूछकर ही कक्षा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जबकि इसे एक संपूर्णतावादी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

जिले की शैक्षिक चुनौतियों को देखें तो यह भी जरूरी लगता है कि जिले की शैक्षिक व्यवस्था का फोकस स्कूल के सीखने–सिखाने पर किस तरह से बने। इस दिशा में डायट व जिला परियोजना कार्यालय द्वारा रणनीति बनाई जानी चाहिए। अकसर फील्ड में शिक्षकों से यह बात उभरकर आती है कि हमें अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है, इस कारण स्कूल की पढ़ाई–लिखाई बाधित होती है। कभी भवन निर्माण के काम में लगाया जाता है। कभी सूचनाओं के संकलन में। उनका कहना यह होता है कि कभी यह बात नहीं होती कि उनकी कक्षाओं में क्या पढ़ाई–लिखाई हो रही है? बच्चे क्या सीख रहे हैं? कितना सीख रहे हैं? ''कौन बच्चे नियमित स्कूल आ पा रहे हैं?'' कौन नहीं आ पा रहे हैं? आदि–आदि। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था की अकादमिक व प्रशासनिक व्यवस्था साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करें।

इस साल से प्राइवेट विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा में कुछ सरकारी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर शिक्षकों के साथ कोई गहराई से विचार–विमर्श भी नहीं किया गया है। इससे लगता है कि सभी स्कूलों की गुणवत्ता से ध्यान हटाकर सरकारी विद्यालयों की एक और श्रेणी तैयार की जा रही है। यहां ध्यान देना जरूरी है कि सभी स्कूलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न रिपोर्टों में यह बात भी उभरी है कि पांचवी कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत भी बच्चे पढ़ने का अपेक्षित स्तर हासिल नहीं कर पाते। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही स्कूलों की अनुसमर्थन प्रणाली किस तरह से सुदृढ़ हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत डायट को शिक्षकों के पेशेवर विकास पर काफी जोर दिया गया है, इस दिशा में ठोस योजना बनाने की जरूरत है। यह मुद्दा हाल के वर्षों में काफी शिद्दत से उभरा है और यह माना जा रहा कि पाठ्यचर्या और पाठय–पुस्तकों के बदलाव की दिशा में कुछ काम किया गया है। अब जरूरत है ऐसे शिक्षक तैयार करने की जो एन.सी.एफ–2005 की दिशा में काम कर पाएं।

यह कहा जा सकता है कि जिले की शैक्षिक गुणवत्ता पर फोकस ढंग ही से। सभी संस्थाओं को मिलकर एक सुविचारित योजना के अनुसार काम करने की जरूरत है। इस दिशा में शिक्षा व्यवस्था द्वारा पहल की जानी चाहिए। इस पहल में शिक्षकों की भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए।